उत्तर प्रदेश

ई-संदेश

13 जून, 2018 • वर्ष 1, अंक 21

सात दिन – सात पृष्ठ

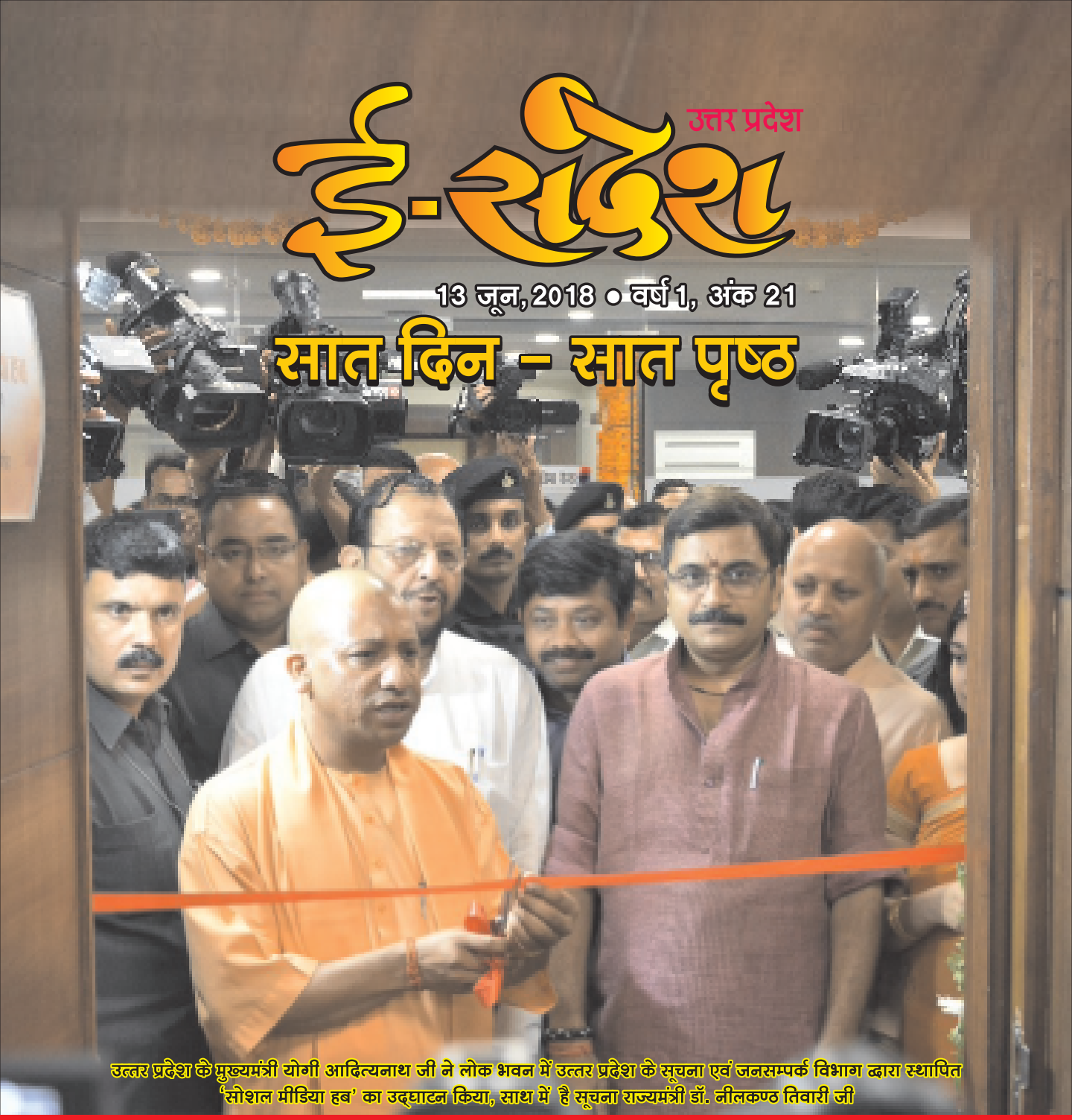

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने लोक भवन में उत्तर प्रदेश के सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग द्वारा स्थापित 'सोशल मीडिया हब' का उद्घाटन किया, साथ में है सूचना राज्यमंत्री डॉ. नीलकण्ठ तिवारी जी

- सोशल मीडिया हब का उद्घाटन
- जे.ई./ए.ई.एस. के मरीजों की संख्या में भारी कमी
- सीतापुर में लगेगा पुआल से ईंधन बनाने का कारखाना
- ग्राम प्रधानों से मुख्यमंत्री जी का सीधा संवाद
- उत्तर प्रदेश में शूटिंग पर मिलेगा निर्माताओं को सहयोग
- 'साफ नीयत–सही विकास' के लिए संकल्पित है सरकार
- ब्रज क्षेत्र में है पर्यटन की अपार संभावनायें

संकल्प से सिद्धि की ओर अग्रसर उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश

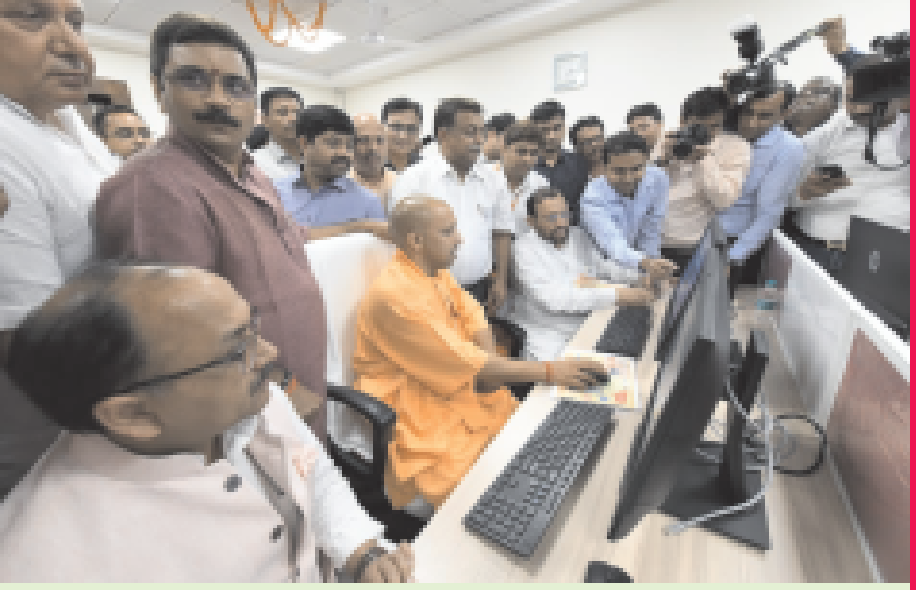

आमजन से संवाद का सशक्त जरिया है सोशल मीडिया

शासन की योजनाओं की जानकारी आमजन तक पहुंचाने में सोशल मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका है। वर्तमान में सोशल मीडिया तेजी से उभरा है। इसने लोगों व देशों के बीच की दूरियां घटायी हैं। 'वसुधैव कुटुम्बकम' के भाव को चरितार्थ करने में सोशल मीडिया अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहा है।

मुख्यमंत्री जी ने लोक भवन में उत्तर प्रदेश के सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग द्वारा स्थापित **'सोशल मीडिया हब'** के उद्घाटन के अवसर पर यह विचार व्यक्त किए।

प्रधानमंत्री जी का करना होगा अनुसरण

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा लॉन्च किया गया 'नमो' एप तथा ऑनलाइन प्लेटफार्म 'mygov.in' देशवासियों को विकास और सुशासन की दिशा में आगे ले जा रहा है। इसका अनुसरण करते हुए राज्य सरकार के सोशल मीडिया को आगे बढ़ना होगा।

सोशल मीडिया द्वारा आमनज को मिल रही शासकीय योजनाओं की जानकारी

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि शासकीय नीतियों, कार्यक्रमों व योजनाओं की जानकारी लाभार्थी एवं आमजन तक पहुंचना जरूरी है। इनकी जानकारी मिलने से आम जनता सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाओं को बेहतर तरीके से जान सकेगी। यह उसे सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा।

ग्रामीण स्तर तक योजनाओं को पहुंचाने में सहायक सोशल मीडिया

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक शासकीय योजनाओं व कार्यों की तथ्यात्मक जानकारी आसानी से पहुंचती है। वहीं दूसरी ओर उसका फीडबैक भी प्राप्त होता है। जनता को अधिकार सम्पन्न बनाते हुए उनकी सहायता और जरूरतों को पूरा करने में सोशल मीडिया अपना कार्य कर रहा है। 60 हजार ग्राम पंचायतों के माध्यम से सोशल मीडिया सरकारी योजनाओं को ग्रामीण स्तर तक पहुंचा सकता है।

समाज व राष्ट्र के लिए उपयोगी तथ्यों के मद्देनजर सकारात्मक व संतुलित दृष्टिकोण अपनाते हुए सोशल मीडिया हब को कार्य करना होगा, तभी जनहित और लोक कल्याण की दिशा में सार्थक व प्रभावी भूमिका अदा की जा सकेगी।

सोशल मीडिया की प्रभावी भूमिका से कार्यों में तेजी व पारदर्शिता आएगी तथा भ्रष्टाचार पर प्रहार होगा। समाज के वंचित व जरूरतमंद लोगों सहित अन्तिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के विकास के लिए सोशल मीडिया सक्रिय योगदान कर सकता है।

– योगी आदित्यनाथ
मुख्यमंत्री

कवर स्टोरी

आजादी के 70 वर्षों के दौरान मीडिया का क्रमिक विकास हुआ है। पहले न्यूज प्रिण्ट हुआ करता था, फिर रेडियो आया, उसके बाद टेलीविजन का विस्तार हुआ और अब सोशल और वेब मीडिया सार्थक व प्रभावी भूमिका के साथ उभरा है। साथ ही, यह 'गेम चेंजर' भी बना है। आज के दौर में इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती। सरकार की योजनाओं को इनके माध्यम से लोगों तक आसानी से पहुंचाया जा सकता है। सोशल मीडिया की भूमिका सहभागी लोकतंत्र को सशक्त बनाती है। इसका सकारात्मक उपयोग किया जाना चाहिए, तभी विश्वसनीयता को बरकरार रखा जा सकेगा।

– सिद्धार्थ नाथ सिंह
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री, उ.प्र.

वर्तमान परिदृश्य में सोशल मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका है। वर्ष 2014 के बाद से सोशल मीडिया का ग्राफ तेजी से बढ़ा है। सरकारी योजनाओं और उपलब्धियों के प्रचार–प्रसार में यह सशक्त भूमिका अदा कर रहा है। तथ्यात्मकता पर फोकस करते हुए सकारात्मक दृष्टिकोण से सोशल मीडिया को कार्य करना होगा। जनपद तथा निचले स्तर तक शासकीय योजनाओं को आम आदमी तक पहुंचाने की रणनीति पर कार्य किया जाना चाहिए। यह भी ध्यान रखना होगा कि जल्दबाजी में कोई त्रुटि न हो।

– श्रीकान्त शर्मा
ऊर्जा मंत्री, उ.प्र.

जनता तक पहुंचने और उसका फीडबैक प्राप्त करने के लिए सोशल मीडिया दोतरफा माध्यम है। शासकीय नीतियों के प्रचार–प्रसार में इसकी भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग इसके महत्व को समझकर आगे बढ़ रहा है।

– डॉ. नीलकण्ठ तिवारी
सूचना राज्यमंत्री, उ.प्र.

मुख्यमंत्री जी के अथक प्रयासों का दिखने लगा असर

जे.ई./ए.ई.एस. के मरीजों की संख्या में भारी कमी

बेहतर प्रयासों का परिणाम

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सरकार के अद्वितीय प्रयासों से जे.ई./ए.ई.एस. के मरीजों की संख्या एवं उनकी मृत्यु दर में भारी कमी आयी है। पूर्व में जहाँ जनवरी से जून 2017 के मध्य जे.ई./ए.ई.एस. से मरने वाले मरीजों की दर 18.3 प्रतिशत थी, वह घटकर इस समय मात्र 8.8 प्रतिशत रह गयी है। जिला चिकित्सालय एवं ई.टी.सी. केंद्रों में चिकित्सा व्यवस्था सुदृढ़ होने के उपरांत से गोरखपुर के बी.आर.डी. मेडिकल कॉलेज में जे.ई./ए.ई.एस. के मरीजों की भर्ती का दबाव भी कम हुआ है। जनवरी से जून 2017 के मध्य जे.ई./ए.ई.एस. के मरीजों का दबाव 53 प्रतिशत था, वह घटकर अब 17 प्रतिशत रह गया है।

गत वर्ष कुल मरीजों में 47 प्रतिशत मरीज स्क्रब टाईफस के थे परन्तु इस वर्ष ए.ई.एस. पर नियंत्रण को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए व्यापक स्तर पर साफ सफाई तथा वेक्टर कण्ट्रोल कार्यवाही करवाई गयी, जिसके कारण इस वर्ष कुल ए.ई.एस. रोगियों में स्क्रब टाईफस के रोगियों का प्रतिशत मात्र 1.1 प्रतिशत रह गया हैं।

जे.ई./ए.ई.एस. से सबसे ज्यादा प्रभावित गोरखपुर एवं बस्ती मंडल के 7 जनपदों में 15 जुलाई से दस्तक अभियान का द्वितीय चरण आरम्भ किया जाएगा, जिसका मुख्य उद्देश्य इस बीमारी पर प्रभावी नियंत्रण पाने के लिए व्यापक टीकाकरण करने के साथ ही जनसामान्य को इसके प्रति जागरूक करना है।

सरकार और टाटा ट्रस्ट मिलकर रोकेंगे दिमागी बुखार

दिमागी बुखार की रोकथाम, उपचार एवं जनजागरूकता हेतु उत्तर प्रदेश सरकार एवं टाटा ट्रस्ट के बीच एक MOU किया गया है। इस साझा कार्यक्रम के अंतर्गत जनपद गोरखपुर तथा सिद्धार्थनगर में मोबाइल मेडिकल वाहन के माध्यम से दिमागी बुखार के रोगियों के त्वरित निदान एवं उपचार की व्यवस्था टाटा ट्रस्ट की ओर से की जाएगी साथ ही जनपद गोरखपुर के पिपराईच ब्लॉक एवं सिद्धार्थनगर के उसका बाजार ब्लॉक को दिमागी बुखार के नियंत्रण एवं उपचार हेतु आदर्श स्वास्थ्य केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा।

चिकित्सकयुक्त मोबाईल वाहन दिमागी बुखार प्रभावित क्षेत्रों का भ्रमण कर रोगियों की जाँच एवं इलाज करेंगे, साथ ही साथ क्षेत्र में दिमागी बुखार के संबंध में जनजागरूकता भी फैलाऐंगे।

इसके अलावा टाटा ट्रस्ट द्वारा इन दोनों ब्लॉक में दिमागी बुखार हेतु प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं भी उपलब्ध कराई जाएगी। इस गतिविधि का मूल उद्देश्य दिमागी बुखार के कारण होने वाली विकलांगता तथा मृत्यु दर पर नियंत्रण करना है।

सीतापुर में लगेगा पुआल से ईंधन बनाने का कारखाना

स्वच्छ भारत मिशन के तहत सीतापुर के चयनित 318 गॉव 15 अगस्त तक होंगे ओ.डी.एफ.

गांवों में कैम्प लगाकर लोगों को दिया जायेगा सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ

पं. दीनदयाल उपाध्याय ने वर्षो पहले ग्राम स्वराज का मूलमंत्र दिया था। ग्राम स्वराज का अर्थ है गांव में सभी के लिए शिक्षा, पेयजल सहित तमाम मूलभूत सुविधाओं से गांव के लोग स्वयं आत्मनिर्भर हों। सीतापुर जनपद के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से जनपद में पुआल से ईंधन बनाने का कारखाना लगेगा, ताकि उन्हें रोजगार के लिए पलायन न करना पड़े। यह विचार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सीतापुर में ग्राम स्वराज अभियान के तहत चयनित 318 गांवों के ग्राम प्रधानों से सीधे संवाद के अवसर पर व्यक्त किए।

वर्ष 2022 तक सबको सुलभ होगा आवास

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि महात्मा गांधी जी के सपनों को साकार करने का कार्य सही मायने में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने किया। प्रधानमंत्री जी के संकल्प के अनुरूप कार्य करते हुए प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2022 तक प्रत्येक व्यक्ति को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास मुहैया कराए जाएंगे। उत्तर प्रदेश में 72 लाख 50 हजार पात्र महिलाओं को उज्ज्वला योजना के अन्तर्गत गैस कनेक्शन दिए गए हैं। इस वर्ष सीतापुर के 70 हजार लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास मिले हैं।

'साफ नीयत–सही विकास' के लिए संकल्पित है सरकार

'साफ नीयत, सही विकास' के लिये राज्य सरकार संकल्पित है। केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार की लाभार्थीपरक योजनाओं को ग्राम स्तर पर लागू किए जाने तथा विकासपरक योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को पारदर्शी एवं समयबद्ध ढंग से उपलब्ध कराने हेतु सरकार पूर्ण निष्ठा के साथ कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री जी ने जनपद उन्नाव में ग्राम स्वराज अभियान के तहत 131 ग्रामों के प्रधानों से सीधे संवाद के अवसर पर यह विचार व्यक्त किए।

विकास की धारा से वंचित लोगों को लाभ

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि विकास की धारा से वंचित लोगों को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, सौभाग्य, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा, मिशन इन्द्रधनुष, वृद्धावस्था, दिव्यांग, विधवा पेंशन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, राशन कार्ड अन्त्योदय/पात्र गृहस्थी, अनुसूचित जाति/जनजाति के लोगों के लिये शादी अनुदान एवं निःशुल्क बोरिंग योजना तथा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनाओं को लागू कर पात्र व्यक्तियों को लाभ दिया जा रहा है।

ग्राम स्वराज अभियान के तहत लाभ

ग्राम स्वराज अभियान के तहत 14 अप्रैल से 5 मई, 2018 के मध्य इन योजनाओं को मिशन के तौर लेते हुए कार्य किया गया। शिक्षा, स्वास्थ्य एवं विद्युत की व्यवस्था से चयनित ग्रामों को ग्राम स्वराज योजना के तहत संतृप्त किया गया है

उन्होंने ग्राम प्रधानों से कहा कि जिस प्रकार सम्पूर्ण समाधान दिवस एवं थाना दिवस का आयोजन जिला प्रशासन द्वारा होता है उसी तर्ज पर अपनी–अपनी ग्राम सभाओं में कमेटियों का गठन कर ग्राम समाधान दिवस आयोजित करें, ताकि भूमि एवं ग्रामों से सम्बन्धित छोटे–छोटे विवादों का स्थानीय स्तर पर, सम्बन्धित विभाग के अधिकारियों को बुला कर, हल निकाला जा सके। उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन पर जोर देते हुये कहा कि व्यक्तिगत शौचालय ज्यादा से ज्यादा बनवाये जायें। ग्राम पंचायतें इस अभियान का हिस्सा बनें जिससे अधिक से अधिक लोगों को इसका फायदा मिल सके। ■

ग्राम प्रधानों से सीधा संवाद कर सीएम ने जाना विकास योजनाओं का हाल

ग्राम स्वराज अभियान का उद्देश्य अधिक से अधिक पात्र लोगों को शासन की योजनाओं का लाभ दिलाना है। इसके लिए जनता के द्वार पर आकर केन्द्र व प्रदेश सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं के सम्बन्ध में जानकारी दी जा रही है। अधिक से अधिक लोग शासन की योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकें, इसके लिए आवश्यक है कि लाभान्वित लोग अन्य जरूरतमन्दों को योजनाओं की जानकारी दें।

–मुख्यमंत्री

प्रत्येक माह एक दिन आयोजित होगा ग्राम समाधान दिवस

वाराणसी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र लाभार्थियों को भेदभाव रहित एवं पारदर्शी तरीके से मुहैया कराए जाने में ग्राम प्रधानों को सक्रिय भूमिका का निर्वहन किए जाने पर जोर देते हुए कहा कि वे अपनी ग्राम सभाओं को आदर्श गांव बनाएं।

ग्रामीण जनता और जनप्रतिनिधिगणों की जागरूकता से गांव की तस्वीर बदलने में समय नहीं लगेगा। ग्रामीण जनता की शिकायत एवं समस्याओं का समाधान गांव स्तर पर ही किया जाएगा। इसके लिए ग्राम प्रधानों द्वारा गांव में प्रत्येक महीने के एक दिन ग्राम समाधान दिवस आयोजित किया जाएगा। इससे ग्रामवासियों की समस्याएं गांव स्तर पर ही निस्तारित हो सकेंगी और उन्हें बेवजह तहसील एवं जिला मुख्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।

ग्राम प्रधान समाज की वह कड़ी हैं, जो अपने ग्राम की दशा व दिशा दोनों ही परिवर्तित कर सकते हैं। ग्राम प्रधानों को अपनी सकारात्मक सोच से भेदभाव रहित ग्राम के विकास में अपना योगदान देना होगा। ग्राम प्रधान जब चुनाव लड़ता है, तो वह व्यक्ति विशेष अथवा परिवार विशेष का सदस्य होता है, परन्तु जब वह निर्वाचित होकर आता है, तो वह सर्वजन का सदस्य हो जाता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जनपद लखीमपुर खीरी में ग्राम स्वराज अभियान के तहत चयनित ग्रामों के 'ग्राम प्रधानों से संवाद' कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुय यह विचार व्यक्त किए।

ग्राम प्रधान करें परिजनों जैसा व्यवहार

इस अवसर पर मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ग्राम प्रधान अपने गांव में 'सबका साथ सबका विकास' की अवधारणा को आत्मसात करते हुए ग्राम के प्रत्येक व्यक्ति के साथ अपने परिजन सा व्यवहार कर शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ मुहैया कराएं। तभी गांव में खुशहाली एवं भाइचारे की भावना को बल मिलेगा और लोगों का जीवन सुखमय व जीवन स्तर ऊंचा उठेगा। शासन द्वारा संचालित कल्याणकारी

> **ग्राम प्रधान जनता को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करें।**
>
> **–मुख्यमंत्री**

योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, यह सरकार का नैतिक दायित्व ही नहीं, बल्कि परम कर्तव्य भी है। ग्राम प्रधान जनता में जागरूकता लाएंगे, ताकि वह अपने अधिकारों के प्रति सजग हो और योजनाओं का लाभ उठा सके।

हर पात्र व्यक्ति को मिले लाभ

मुख्यमंत्री जी ने ग्रामीणों से एक–एक कर शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं के संबंध में स्थलीय सत्यापन किया और किन्हीं कारणवश कल्याणकारी योजनाओं से वंचित रह गये पात्र व्यक्तियों को सम्बन्धित विभाग कैम्प लगाकर लाभान्वित करने के निर्देश दिए।

सभी पात्रों तक प्रत्येक योजना का लाभ बिना किसी परेशानी के पहुंचे, इसके लिए मुकम्मल व्यवस्था की गयी है। बिचौलिया प्रथा समाप्त कर योजनाओं की धनराशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जा रही है। सरकार का प्रयास है कि किसी भी योजना का कोई भी पात्र लाभ पाने से वंचित न रहे।

भारत का विकास इंजन है उत्तर प्रदेश : मुख्यमंत्री

राज्य सरकार ने प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कई नीतियां तैयार कर उन्हें लागू किया गया है। अन्य आवश्यक नीतियों पर भी तेजी से कार्य चल रहा है। अमेरिकी कम्पनियों के लिए उत्तर प्रदेश में निवेश की अपार सम्भावनाएं मौजूद हैं। राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति–2017 घोषित की है, जो आकर्षक प्रोत्साहन प्रदान करती है।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी अमेरिका के राजदूत श्री केनेथ आई. जस्टर से मुलाकात के दौरान यह उद्गार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश भारत का विकास इंजन है तथा देश की सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य होने के साथ ही देश की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जो तेजी से आगे बढ़ रही है।

उ.प्र. है विश्व की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था

इस अवसर पर अमेरिकी राजदूत ने कहा कि अमेरिका के उत्तर प्रदेश के साथ आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, वाणिज्यिक सम्बन्ध हैं जो बहुत पुराने हैं। उत्तर प्रदेश विश्व की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश तेजी से विकास कर रहा है। प्रदेश में औद्योगिक निवेश के लिए अनुकूल वातावरण है और अमेरिका उत्तर प्रदेश के साथ अपने सम्बन्ध और सुदृढ़ करना चाहता है।

गेहूँ किसानों को किया गया रू. 8234.54 करोड़ का भुगतान

अब तक 47.56 लाख मीट्रिक टन हुई गेहूँ खरीद

रबी क्रय वर्ष 2018–19 में मूल्य समर्थन योजना के तहत विभिन्न गेहूँ कय केन्द्रों के माध्यम से अब तक 47.56 लाख मीट्रिक टन गेहूँ की खरीद की जा चुकी है। पिछले साल इसी समयावधि में लगभग 31.68 लाख मीट्रिक टन गेहूँ की खरीद हुई थी। पिछले साल की तुलना में इस साल लगभग डेढ़ गुना अधिक खरीद हुई है। इस योजना से अब तक 9,66,753 किसान लाभान्वित हुए हैं तथा किसानों को 8234.54 करोड़ रूपये का भुगतान आर.टी.जी.एस. के माध्यम से किया जा चुका है। इस वर्ष 50 लाख मीट्रिक टन गेहूँ खरीद का लक्ष्य रखा गया है, जिसके सापेक्ष लगभग 95 प्रतिशत खरीद की जा चुकी है। ■

'एक जनपद एक उत्पाद' योजना के तहत स्थापित उद्योगों की स्थिति होगी सुदृढ़

पं. दीनदयाल ग्रामोद्योग रोजगार योजना के तहत मिलेगा 13 प्रतिशत तक ब्याज उपादान

उत्तर प्रदेश सरकार ने ''एक जनपद एक उत्पाद'' योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित उद्योगों को नवीनतम् तकनीक से सुसज्जित करने एवं उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए पं. दीनदयाल ग्रामोद्योग रोजगार योजना शुरू की है। इस योजना के माध्यम से प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम से वित्तपोषित/स्थापित इकाइयों को ब्याज उपादान की सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी।

योजना का मुख्य उद्देश्य गॉवों में बढ़ती बेरोजगारी तथा ग्रामीण शिक्षित बेरोजगार युवकों का शहरों की ओर पलायन रोककर लोगों को उनके गांव में रोजगार मुहैया कराकर आत्मनिर्भर बनाना है।

इस योजना से जिला उद्योग केन्द्र, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग तथा उ.प्र. खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा सहायतित समस्त ग्रामीण इकाइयां लाभान्वित होंगी। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्त पोषित इकाईयों को इस योजना के माध्यम से 13 प्रतिशत तक ब्याज उपादान की सुविधा 03 वर्षो तक उपलब्ध कराई जायेगी। योजना की समस्त प्रक्रिया ऑन–लाइन की जायेगी।

ब्रज क्षेत्र में है पर्यटन की अपार संभावनायें

ब्रज क्षेत्र में पर्यटन की अपार सम्भावनाएं मौजूद हैं। ऐसे में इस क्षेत्र का समुचित और सुनियोजित विकास अत्यन्त आवश्यक है, ताकि पर्यटकों को कोई असुविधा न हो।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद की प्रथम बैठक के दौरान कहा कि ब्रज तीर्थ के विकास के लिए कार्य योजना तैयार की जाएगी और इस पर फेजवाइज़ काम किया जाएगा। इस क्षेत्र के विकास में कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत कौन से कार्य कराए जा सकते हैं, उन्हें चिन्हित किया जाएगा।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ब्रज क्षेत्र में स्थानीय स्तर पर कराए जा रहे निर्माण कार्यों में लोकल आर्किटेक्चर का ध्यान रखा जाएगा और इनमें वहां की संस्कृति भी प्रतिबिम्बित की जाएगी। ब्रज क्षेत्र के स्थानीय पारम्परिक भवन स्थापत्य का ध्यान रखा जाएगा।

पर्यटकों और परिक्रमार्थियों की सुविधा के लिए इस क्षेत्र के महत्वपूर्ण स्थलों पर विस्तृत सूचना–पट लगाए जाएंगे, ताकि उन्हें पूरी जानकारी मिल सके। पूरे ब्रज तीर्थ क्षेत्र की प्रकाश व्यवस्था चुस्त–दुरुस्त की जाएगी। जहां–जहां आवश्यकता हो, वहां हाईमास्ट लगाए जाएंगे, ताकि पर्यटकों को कोई असुविधा न हो और शहर का आभा मण्डल बन सके। यात्रियों की सुविधा के लिए धर्मशालाएं और रैन बसेरे भी स्थापित किए जाएंगे और पर्यटकों की सुरक्षा के लिए टूरिस्ट पुलिस की तैनाती की जाएगी।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली उन्हें अद्वितीय बनाती है : डॉ. दिनेश शर्मा

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कर्म के प्रति निष्ठावान, जनता के प्रति समर्पित और अपनी बात के प्रति एक निष्ठ भाव रखने वाले कर्मयोगी हैं। योगी आदित्यनाथ जी जबसे मुख्यमंत्री बने, उन्होंने मठ और मंदिर के संस्कारों में कहीं कमी नहीं आने दी। मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने अपनी दिनचर्या में कटौती की। रात में 12 बजे भी वह काम करते मिलेंगे और सुबह सात बजे के कार्यक्रम में भी पूरी तरह तैयार दिखते हैं। उनका कठिन परिश्रम और दृढ़ प्रतिज्ञ होकर काम करने का तरीका उनकी विशिष्टिता है। उनके कार्य करने की यही शैली उन्हें अद्वितीय बनाती है।

उपमुख्यमंत्री डा दिनेश शर्मा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के जीवन पर आधारित वरिष्ठ पत्रकार रामेंद्र सिन्हा द्वारा लिखित पुस्तक 'कर्मयोगी' के लोकार्पण समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री जी का परिवार आज भी काफी साधारण एवं सरल जीवन व्यतीत कर रहा है। राजनीति में यह बहुत बड़ी आशा की एक किरण है जो हम सबमें विश्वास पैदा करती है कि राजनीति में शुचिता, पारदर्शिता और उच्च मापदंड आज भी जीवित हैं और उस जीवन को जीने वाले चरित्र के जीवन पर रचित पुस्तक को कर्मयोगी नाम दिया गया है।

उत्तर प्रदेश में शूटिंग पर मिलेगा निर्माताओं को सहयोग

उत्तर प्रदेश में फिल्म निर्माण की असीम सम्भावनाएं हैं। इसके दृष्टिगत राज्य सरकार फिल्म निर्माण गतिविधियों को प्रोत्साहित कर रही है। यहां पर शूटिंग करने वाले फिल्म निर्माताओं को हर सम्भव सहयोग व सुविधा प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से भेंट के दौरान फिल्म अभिनेता संजय दत्त ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाओं के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश में फिल्म निर्माण की ओर फिल्म निर्माता आकर्षित हो रहे हैं। राज्य सरकार फिल्म निर्माण से सम्बन्धित गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए अच्छा कार्य कर रही है। उन्होंने वर्ष 2018 में लागू की गई उत्तर प्रदेश की संशोधित फिल्म नीति के तहत हिन्दी एवं उत्तर प्रदेश की क्षेत्रीय भाषाओं के साथ ही उत्तर प्रदेश में बनने वाली अंग्रेजी एवं देश की अन्य भाषाओं की फिल्मों को भी अनुदान की श्रेणी में शामिल किए जाने की सराहना करते हुए कहा कि इससे प्रदेश में बनने वाली फिल्मों की संख्या में बढ़ोत्तरी होगी।

12 जून 2018 को सम्पन्न प्रदेश कैबिनेट की बैठक में लिए गए

महत्वपूर्ण निर्णय

25 करोड़ तक लागत बढ़ोत्तरी को विभाग स्वयं कर सकेगे स्वीकृत

योजनाओं के शीघ्र क्रियान्वयन में आने वाली अड़चनों को दूर करने के उद्देश्य से सरकार ने परियोजनाओं की पुनरीक्षित लागत के प्रस्तावों में मूल्यांकन की व्यवस्था में संशोधन को स्वीकृति प्रदान कर दी है।

नई व्यवस्था के अनुसार 25 करोड़ रूपये तक की पुनरीक्षित लागत के प्रस्ताव को प्रशासकीय विभाग स्वयं स्वीकृति प्रदान कर सकेंगे। इससे अधिक के प्रस्तावों का परीक्षण ही व्यय वित्त की समिति को प्रेषित किया जायेगा। सरकार के इस निर्णय से परियोजनाओं के त्वरित गति से पूर्ण होने में सहायता मिलेगी।

- राज्य पोषण मिशन दूर करेगा बच्चों में कुपोषण
- पीएसी ने प्रदान की लखनऊ-बहराईच हाईवे के लिए जमीन
- वाराणसी में बनेगी रैपिड ऐक्शन फोर्स (आरएएफ) की नई वाहिनी
- दो विवाह करने वाले नहीं बन सकेंगे सिपाही
- मुजफ्फरनगर-सहारनपुर राजमार्ग पर देना होगा पथकर

अभूतपूर्व हैं केन्द्र तथा प्रदेश सरकार की उपलब्धियाँ

केन्द्र सरकार के चार वर्ष के कार्यकाल की विभिन्न योजनाओं से देश के करोड़ों परिवार लाभान्वित हो रहे हैं और आज अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर देश के गौरव में वृद्धि हुई है। सरकार की साफ नीयत और सही विकास की दृष्टि से देश के गरीब, शोषित और वंचित वर्ग के जीवन में व्यापक बदलाव आया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कुशल नेतृत्व में आयुष्मान भारत योजना के अन्तर्गत 10 करोड़ परिवारों को प्रतिवर्ष प्रति परिवार 5 लाख रूपये का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जायेगा, जबकि उज्जवला योजना के अन्तर्गत 3.8 करोड़ गरीब महिलाओं को नि:शुल्क एल.पी.जी. कनेक्शन दिये गये, मिशन इंद्रधनुष के अन्तर्गत 528 जिलों के 3.15 करोड़ बच्चों का टीकाकरण किया गया तथा महिलाओं और शिशुओं को रोगों से बचाने हेतु 80 लाख से अधिक गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण कराया गया, आम लोगों को सस्ती दर पर दवायें उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 3000 जन औषधि केन्द्रों की स्थापना की गयी।

वर्तमान शासनकाल में भारत वैश्विक ग्रोथ का इंजन बना। विश्व के सकल घरेलू उत्पाद में 2013 में भारत का हिस्सा 2.43 प्रतिशत था, जो 2017 में बढ़कर 3.08 प्रतिशत हो गया। विश्व सकल घरेलू उत्पाद में भारत का हिस्सा 2005 के 1.75 से बढ़कर 2013 में 2.43 हुआ था। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से प्रत्येक गांव को जोड़ने की मुहिम के अन्तर्गत विगत 4 वर्षों में लगभग 1.69 लाख किलोमीटर लंबी ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया गया। ग्रामीण सड़कों की पहुंच वर्ष 2014 के 56 प्रतिशत से बढ़कर 82 प्रतिशत के स्तर पर पहुंच गई है। भारत एक तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था है और आज पूरी दुनिया में भारत की साख बढ़ी है। ■

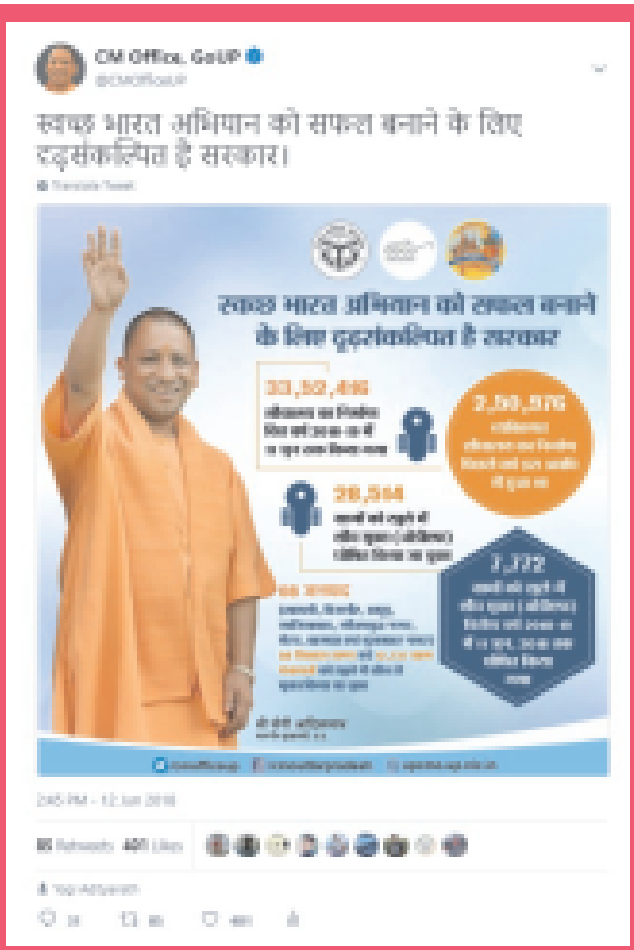

सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश के लिए, निदेशक डॉ. उज्ज्वल कुमार द्वारा प्रकाशित. सम्पादक : सुहेल वहीद अंसारी